Shri Morarji Desai: They are not entitled to any compensation under the new Act or ordinance

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास

{श्री सरजू पाण्डे :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये केन्द्रीय सरकार की मुख्य योजनाएं क्या हैं, और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में निजी उद्योगों के विकास के लिये कितनी धन राशि दी है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) तथा (ख) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५]

श्री भक्त दर्शन इस विवरण में जो कृत्रिम रबड़ बनाने के संयंत्र और एल्यूमीनियम बनाने के संयंत्र का जिक्र किया गया है ये कब तक कागज की फायलों में रहेंगे और कब तक वास्तव में चलाये जायेंगे ?

श्री मनुभाई शाह इस का बहुत बार जिक्र हो चुका है। यह मामला कागज से आगे चल चुका है और इस का प्राथमिक नक्शा तैयार हो चुका है।

वाराणसी में दियासिलाई का कारखाना

*६३९ **श्री रूप नारायण** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष वाराणसी में दियासलाई का एक कारखाना खोलने के लिये कोई राशि मंजूर की थी ;

(ख) यदि हां तो कितनी ;

(ग) क्या यह सच है कि उस कारखाने के न खुलने के कारण वह राशि व्यपगत हो गई;

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां थीं, और

(ङ) क्या भारत सरकार का इस काम के लिये और कुछ राशि पुन मंजूर करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में सरकारी ढंग पर दियासलाई का कारखाना खोलने की एक योजना प्रस्तुत की है।

(ख) १,१०,००० रु० का अनुदान, १,७५,७०० रु० का ऋण

(ग) जी हां।

(घ) इस सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई यह है कि तीलिया और डिबिया बनाने की लकड़ी किफायती दरों पर उपलब्ध नहीं होती। इसलिये औद्योगिक सरकारी ढंग पर चलने वाला दियासलाई का यह कारखाना प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकेगा।

(ङ) मामले की जांच की जा रही है जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह योजना कारगर बनाई जा सकती है या नहीं।

श्री रूप नारायण क्या मैं जान सकता हूं कि इस फैक्टरी को चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है ?

श्री मनुभाई शाह यह जिम्मेदारी इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव पर है न स्टेट गवर्नमेंट पर है और न सेंट्रल गवर्नमेंट पर।

श्री रूप नारायण क्या मैं जान सकता हूं कि इसके विषय में कोई प्रारम्भिक कार्रवाई की गई है कोई बोर्ड या कमेटी बनाई गई है जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई है ?